POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 02

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 फरवरी, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! चार राज्यों के विधानसभा चुनावों ने सभी राजनीतिक दलों को बहुत कुछ सीखने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली में नई नवेली 'आम आदमी पार्टी' को मिले मतदाताओं के समर्थन ने सभी को अचरज में डाल दिया।

इसके बाद 'आम आदमी पार्टी' की सरकार ने जनहित में जिस तरह की नई-नई शुरुआतें की हैं, उससे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां भी बदलाव की भूमिका में नजर आने लगी हैं। इससे लोगों में व्यवस्था परिवर्तन की आस जगी है।

पिछले 46 साल से अटका लोकपाल बिल तुरत-फुरत पास हो गया। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ कई विधेयक और लाने की बात करने लगे हैं। प्रदेशों में सरकारें अपने मंत्रियों और विधायकों को सादगी की सीख दे रही हैं। सत्ता और आम आदमी के बीच की दूरी कम करने के प्रयास शुरू हुए हैं। जनता को राहत देने वाले कामों पर ज्यादा फोकस होने लगा है।

राजनीतिक दलों को यह अहसास जरूर हुआ है कि देश का आमजन अब जागरूक हो गया है और वह व्यवस्थाओं में सुधार चाहता है। मद्देनजर सभी दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन ला रहे हैं। सादगी और जनसुनवाई पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसे लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत माना जा रहा है।

माता-पिता की सेवा नहीं की तो होगी जेल

माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक जो अपनी निजी आय से अपना गुजारा चलाने में असमर्थ है, अपने बच्चों पर भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। इसके लिए 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' लागू है।

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हर माता-पिता व बुजुर्ग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने बच्चों से कानूनन मासिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वे आवास, भोजन, कपड़े और चिकित्सा सम्बन्धी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए उनसे क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश में न्यायाधिकरण भी स्थापित किए गए हैं, जहां इन मामलों का यथा शीघ्र निपटारा होता है।
- अगर किसी ने उनसे सम्पत्ति हस्तान्तरित करवा ली है, तो सम्पत्ति पाने वाले को सम्पत्ति हस्तान्तरण करने वाले माता-पिता व बुजुर्गों की जरूरतों का पूरा खयाल रखना होगा। अगर सम्पत्ति पाने वाला इसमें असफल रहता है तो सम्पत्ति के हस्तान्तरण को फर्जी करार दिए जाने का प्रावधान भी कानून में है।
- अधिनियम के अनुसार माता-पिता व वृद्धजनों की सही सेवा व देखभाल नहीं करने वालों को अब तीन माह तक की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- राज्य सरकार को भी वृद्धजनों की न्यूनतम आर्थिक स्तर की जरूरतें पूरी करने लायक पेंशन निर्धारित करनी होगी और उनकी चिकित्सा के लिए साधनयुक्त चिकित्सा वार्ड स्थापित करेंगी। जो बुजुर्ग स्वेच्छा से अलग रहता हो तो उसके जान-माल की सुरक्षा के लिए सरकार पर्याप्त पुलिस सतर्कता का भी इन्तजाम करती है।

बिना बिजली कनेक्शन बिल भेजना भारी पड़ा

बस्सी के पाटल गांव निवासी तारा देवी ने उपभोक्ता मंच में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। तारा देवी ने अपने परिवाद में मंच को बताया कि बीपीएल होने के नाते उसने 2009 में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। विभाग ने 26 सितम्बर, 2009 को 29 यूनिट बिजली उपभोग दिखाकर 287 रुपए का बिल उसके घर भिजवा दिया। जबकि उसके घर पर न तो बिजली का कनेक्शन दिया गया था और न ही मीटर लगाया गया था।

उसने इसकी बिजली विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत की तो बजाय गलती स्वीकार करने के उसे जवाब मिला कि बिल जमा करा दो, बिजली कनेक्शन लगने के बाद राशि बिल में समायोजित करली जाएगी। विभाग ने अपनी गलती मानने के बजाय उससे यह भी कहा गया कि अगर बिल जमा नहीं कराया तो आगे भविष्य में उसे कनेक्शन भी नहीं मिलेगा।

उपभोक्ता मंच ने मामले की सुनवाई पर बिना कनेक्शन के बिजली बिल भेजने को सेवा में कमी का दोषी माना। मंच ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बस्सी क्षेत्र के मुख्य अभियंता व एईएन को आदेश दिए है कि वह तारा देवी को 4000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करे।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 32 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2013 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह हैं:

'बढ़ती महंगाई से परेशान आमजन'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2013 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2014 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

सरकारी कामों में बरतें सादगी

राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कलक्टरों को सरकारी कामकाज में सादगी बरतने की नसीयत दी है। आम लोगों के काम पहली प्राथमिकता से पूरे हों। सरकार का फोकस सादगी और जनता को राहत देने वाले कामों पर है। इसी से राजस्थान बदलेगा और जनता के लिए बेहतर कल का निर्माण होगा।

उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा कि वे अपने जिलों में एक-एक बालिका को गोद लें और उनकी लालन-पालन की जिम्मेदारी उठाएं। साथ ही एक-एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करें। जिलों में सफाई, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा व सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाया जाए। सरकार प्रदेश में जल्द सुशासन कानून लागू करेगी।

किसानों को मिलेगा ऋण

रबी सीजन में प्रदेश के किसानों को एक हजार करोड़ रुपए के लघु अवधि के फसली ऋण दिए जाएंगे। साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 10 हजार मीट्रिक टन डीएपी खाद किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

राज्य में 250 नए मिनी बैंक भी खोले जाएंगे। भूमि विकास बैंक के जरिए किसानों को 40 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा 2500 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 15 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराएगा।

किसानों को मिलेंगी नई जानकारियां

सरकार किसानों को कृषि प्रबन्धन के तौर तरीके सिखाएगी। इसके लिए राजस्थान एग्रो कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना शुरू की गई है। स्वयंसहायता समूहों की तर्ज पर किसानों के ग्रुप बनाकर उनसे नए-नए प्रयोग करवाए जाएंगे। इस परियोजना में परंपरागत खेती के अलावा नया करने वाले किसानों को चुना जाएगा।

किसानों को जल बचत, ज्यादा पैदावार, उद्यानिकी व पशुपालन से रोजगार के बारे में बताया जाएगा। सरकार समूह को चार बीघा में खेती करने के लिए बीज, कीटनाशक जैसी जरूरी चीजें मुफ्त देगी। प्रदेश में जयपुर सहित 12 जगहों पर इसकी शुरुआत कर दी गई है।

बनेंगे 70 हजार सहायता समूह

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच साल में 70 हजार स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में औसत रूप से 11 लोग शामिल होंगे। इससे ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा में पक्के व बड़े काम करवाने पर जोर दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों के मकान बनाने तथा गांवों में शौचालय बनाने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता देने का काम भी प्रमुखता से होगा।

परियोजनाएं तय समय पर पूरी हों

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया है। इससे लोगों को पीने का शुद्ध पानी एवं सिंचाई सुविधाएं मिल सकेंगी।

जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की समीक्षा में उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होनी चाहिए। कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा होने में सालों लग जाते हैं, ऐसे में जनता को उसका फायदा समय पर नहीं मिल पाता और लागत भी बढ़ जाती है। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा फव्वारा सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए इंदिरा गांधी नहर की फलोदी लिफ्ट योजना के तहत 500 हेक्टेयर क्षेत्र खोला जाएगा।

करोड़ों खर्च, नतीजा सिफर

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन राज्य के 32 में से 19 जिलों में जल गुणवत्ता जांचने का आंकड़ा लक्ष्य के मुकाबले एक फीसदी को भी पार नहीं कर पाया।

यह कार्यक्रम 2008 से चल रहा है और इसके लिए 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। अब तक करीब 900 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं, लेकिन 19 जिलों में काम ही नहीं हुआ। पेयजल स्त्रोतों की साल में तीन बार जांच का प्रावधान था, लेकिन अधिकतर जिलों में ऐसा नहीं किया गया। विभागीय उदासीनता के चलते किट में काम आने वाला रसायन भी सूख गया।

सुधरें किसानों की हालत

प्रदेश में छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। कई किसान तो खेती से परिवार की जीविका चलाने में भी असमर्थ होते जा रहे हैं। इससे उनका खेती के प्रति रुझान कम हो रहा है।

कई किसान इस वजह से खेती करना छोड़ भी चुके हैं। सरकार की ओर से ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कृषि विभाग को ऐसे किसानों को मुफ्त अथवा कम मूल्य पर अच्छे बीज, खाद व कीटनाशक आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

-गोपाललाल मीणा, सवाई माधोपुर

फालतू खर्चों पर लगाम

हमारे देश में मंत्रियों को दिए जा रहे भत्तों एवं विभिन्न सेवाओं के नाम पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। यह आम जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल है।

दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने इन खर्चों पर लगाम लगाई है। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे मंत्रियों व विधायकों के फालतू खर्चों को कम करने की दिशा में काम कर रही है। जनता भी चाहती है कि खर्चों में कमी करके यह पैसा लोगों की भलाई के कामों में खर्च होना चाहिए। फालतू खर्चों पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को ठोस नीति बनानी होगी।

- बृज किशोर, भरतपुर

चन्द्र मौलि पचरंगिया ग्राम गदर पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' की ओर से जी.जी.मेमन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा झुंझुनू जिले के चिड़ावा निवासी पत्रकार चन्द्र मौलि पचरंगिया को दस हजार रुपए का चैक व प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर 'ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन पत्रकारों को दिए जाते हैं, जिन्होंने जनहित के मामलों को पत्रकारिता के माध्यम से असरदार तरीके से उठाया है। पचरंगिया को यह पुरस्कार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 'कट्स' द्वारा होटल जयपुर पैलेस में आयोजित प्रो-ओर्गेनिक परियोजना के उद्घाटन समारोह में प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2012 के दौरान 'महिलाओं के प्रति हिंसा व उनकी सुरक्षा' विषय पर की गई उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया गया है।

छोटी-छोटी होंगी ग्राम पंचायतें

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि प्रदेश में जल्दी ही पंचायतों का पुनर्गठन होगा। सुविधा की दृष्टि से छोटी-छोटी प्रचायतें बनाई जाएंगी। अभी पंचायतों के बीच दूरी काफी होने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पुनर्गठन से गांवों में विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, जो सरकार को प्रस्ताव के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट देगी।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485